



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 भाद्र 1933 (श0)

(सं0 पटना 478)

पटना, शुक्रवार, 26 अगस्त 2011

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं

25 अगस्त 2011

एस0 ओ0 239, दिनांक 26 अगस्त, 2011—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा 93 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं—

#### संशोधन

1. बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 3 के पश्चात् एक नए नियम 3क का अंतःस्थापन।—बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 3 के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम 3क अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा—

3 क “केन्द्रीयकृत निबंधन इकाई।—(1) नियम 3 में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, ऐसे व्यवहारी द्वारा, जो ऐसे अंचल अथवा ऐसे क्षेत्र में व्यवसाय करते हो जो आयुक्त द्वारा इस निमित्त निर्गत अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाय यथास्थिति, प्रपत्र AI अथवा AIक में निबंधन हेतु आवेदन ऐसे प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा जो उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाय।

(2)(क) उप-नियम (1) के अधीन व्यवहारी द्वारा प्रत्येक आवेदन अधिनियम के अधीन कर-दायित्व की तिथि से सात दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा एवं नियम 3 के उप-नियम (2) में उपबंधित रीति से हस्ताक्षरित एवं सत्यापित किया जायेगा।

(ख) ऐसा आवेदन उप-नियम (1) के अधीन निर्गत अधिसूचना में निर्दिष्ट पदाधिकारी के कार्यालय के काउंटर पर प्रस्तुत किया जायेगा। काउंटर का प्रभारी, यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि आवेदन के सभी स्तम्भ समुचित रूप से भरे गये एवं हस्ताक्षरित एवं सत्यापित हैं—

(i) उस व्यक्ति को इसके बदले एक रसीद निर्गत करेगा, तथा

(ii) कम्प्यूटर में संधारित पंजी VR-I में उसकी विशिष्टियों को दर्ज करेगा:

परन्तु उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी व्यवहारी से ऐसी जानकारी, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा जो वह उचित समझे।

(3) वैसे व्यवहारी के मामले में जिस पर धारा 22 लागू हो, निबंधन के आवेदन के साथ फारम D-I में सही एवं पूर्ण घोषणा संलग्न रहेगी जिसमें फारम में विहित विशिष्टियां दर्ज होंगी और उसके

साथ-साथ व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के दो रंगीन फोटोग्राफ (13.5 से0मी0 X 2.5 से0मी0) लगे रहेंगे।

(4)(क) उप-नियम (1) के अधीन निर्गत अधिसूचना में विहित प्राधिकारी, निबंधन हेतु आवेदन प्राप्त होने पर, अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (2) के अधीन निर्गत अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार आवेदक पर अधिकारिता रखनेवाले अंचल के संबंध में करदाता पहचान संख्या सृजित करेगा।

(ख) खंड (क) के अधीन करदाता पहचान संख्या सृजित किये जाने के पश्चात्, उप-नियम (1) के अधीन निर्गत अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी आवेदक को फारम C-I में निबंधन प्रमाण पत्र यथा शीघ्र, अधिमानित रूप से पंद्रह दिनों के भीतर प्रदान करेगा।

(ग) खण्ड (ख) के अधीन निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र, व्यवसायी के आवेदन में दिये गये पते पर निर्गमन की तिथि से दो दिनों के भीतर निबंधित डाक से प्रेषित किया जायेगा।

(5)(क) प्रपत्र C-I में निबंधन प्रमाण पत्र प्रदान करने के पश्चात्, उप-नियम (1) के अधीन निर्गत अधिसूचना में निर्दिष्ट प्राधिकारी तीन दिनों के भीतर निबंधन हेतु आवेदन की एक प्रति संबंधित अंचल प्रभारी को अग्रसारित करेगा।

(ख) संबंधित अंचल प्रभारी एक महीने के भीतर आवेदन में प्रस्तुत की गई विशिष्टियों का सत्यापन करेगा अथवा करवाएगा। इसके पश्चात् संबंधित अंचल प्रभारी उप-नियम (1) के अधीन निर्गत अधिसूचना में निर्दिष्ट प्राधिकारी को जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर जांच प्रतिवेदन की एक प्रति अग्रसारित करेगा।

(ग) खंड (ख) के अधीन जांच प्रतिवेदन के अनुरूप यदि आवेदन में प्रस्तुत की गई, विशिष्टियों में से कोई असत्य पाई जाती है अथवा आवेदक द्वारा किसी तथ्य का दूरव्यपदेशन किया गया या उसे दबाया गया हो, तो उप-नियम (1) के अधीन निर्गत अधिसूचना में निर्दिष्ट प्राधिकारी, व्यवसायी को, सुनवाई का अवसर देने के बाद, उप-नियम (4) के अधीन प्रदत्त निबंधन प्रमाण पत्र को रद्द कर देगा।

स्पष्टीकरण— इस उप-नियम के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्ति “संबद्ध अंचल प्रभारी” से अभिप्रेत है वह अंचल प्रभारी जिसके क्षेत्राधिकार में व्यवसायी का व्यवसाय स्थल अवस्थित हो।

(6)(क) ऐसे व्यवहारी की दशा में जो बिहार के विभिन्न अंचलों में अवस्थित एक से अधिक जगहों पर अपना करोबार करता हो अथवा किसी ऐसे व्यवहारी की दशा में जिसका बिहार में करोबार की कोई नियत जगह नहीं हो एवं जो राज्य के भीतर प्रत्यक्ष अथवा यात्रा अभिकर्ताओं अथवा विक्रेताओं द्वारा अथवा अन्यथा अपना माल बेचे, तो वह आयुक्त अथवा इस हेतु विशेष रूप से प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करेगा। ऐसे आवेदन के प्राप्त होने पर, आयुक्त अथवा इस हेतु विशेष रूप से प्राधिकृत पदाधिकारी उप-नियम (1) के अधीन निर्गत अधिसूचना में निर्दिष्ट प्राधिकारी को निदेशित कर सकेगा कि वह, निदेश में विनिर्दिष्ट अंचल में, व्यवसायी का निबंधन करे।

(ख) उप-नियम (7) से उप-नियम (5) के प्रावधान इस उप-नियम के अधीन निबंधन के लिए आवेदन पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(7)(क) नियम 4 में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, यदि उप-नियम (4) के खंड (ख) के अधीन स्वीकृत निबंधन प्रमाण-पत्र खो जाय, बर्बाद हो जाय, विकृत हो जाय अथवा दुर्बोध हो, तो ऐसा प्रमाण-पत्र धारक संबंधित अंचल प्रभारी को प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति जारी करने हेतु आवेदन करेगा। ऐसे आवेदन के साथ—

(i) फीस के रूप में एक सौ रुपये का रसीदी कोषागार चालान,

(ii) फारम B-I में क्षतिपूर्ति बंध पत्र संलग्न होगा।

(ख) उक्त प्राधिकारी, उस प्रमाण-पत्र, जिसके खो जाने, नष्ट किये जाने, विरूपित किये जाने अथवा दुर्बोध होने का दावा किया गया था, के बदले दूसरा प्रमाण-पत्र स्वीकृत करने के लिए अग्रसर होगा जिस पर लाल स्याही से “दूसरी प्रति” स्टाम्पित की जायेगी।

(8)(क) नियम 5 में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, प्रत्येक व्यवसायी, जिसका निबंधन उप-नियम 4 के खंड (ख) के अधीन स्वीकृत किया गया हो एवं जिस पर धारा 23 के उपबंध लागू हों उप-नियम (1) के अधीन निर्गत अधिसूचना में विनिर्दिष्ट समुचित प्राधिकारी को, धारा 20 के अधीन कार्रवाई को अनिवार्य बनानेवाले पूर्ण ब्यौरा के बारे में, लिखित रूप में सूचना देगा।

(ख) जहाँ धारा 23 के अधीन व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना अथवा अन्यथा प्राप्त सूचना उप-नियम (1) के अधीन निर्गत अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा, जो प्रपत्र A-I अथवा A-I क में उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी एवं तत्पश्चात् प्रपत्र VR-I में रजिस्टर में दर्ज की गयी किसी सूचना में संशोधन को अनिवार्य बना दे, वहाँ उक्त प्राधिकारी धारा-23 के अधीन अथवा

अन्यथा प्राप्त सूचना की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर प्रपत्र VR-I में रजिस्टर में उपयुक्त संशोधन करेगा।

- (ग) जहां उप-नियम (1) के अधीन निर्गत अधिसूचना में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा धारा 23 के अधीन किसी व्यवहारी द्वारा दी गई अथवा अन्यथा प्राप्त जानकारी से धारा 22 के अधीन दी गयी घोषणा में संशोधन आवश्यक हो जाय, वहां व्यवहारी उक्त प्राधिकारी को पुनरीक्षित घोषणा देगा; जबतक ऐसी पुनरीक्षित घोषणा उक्त प्राधिकारी को प्रस्तुत न कर दी जाय तबतक मूल घोषणा विधिमाम्य और उस व्यवहारी पर बाध्यकारी समझी जाती रहेगी।
- (घ)(i) प्रत्येक निबंधित व्यवसायी जिसे उप-नियम (4) के खंड (ख) के अधीन प्रमाण-पत्र स्वीकृत किया गया हो एवं जिस पर धारा 20 की उप-धारा (2) लागू होती हो, अपना निबंधन प्रमाण-पत्र रद्द करने हेतु उप-नियम (1) के अधीन निर्गत अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष प्रपत्र A-II में अपने निबंधन प्रमाण-पत्र के साथ-साथ तुरत आवेदन करेगा।
- (ii) ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर, के तीन दिनों के भीतर, उप-नियम (1) के अधीन निर्गत अधिसूचना में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी एक प्रति संबंधित अंचल प्रभारी को अग्रसारित करेगा।
- (iii) संबंधित अंचल प्रभारी एक महीने के भीतर आवेदन में प्रस्तुत की गई विशिष्टियों का सत्यापन करेगा अथवा करवाएगा। इसके पश्चात् संबंधित अंचल प्रभारी उप-नियम (1) के अधीन निर्गत अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को, जांच-प्रतिवेदन प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर, जांच-प्रतिवेदन की एक प्रति अग्रसारित करेगा।
- (iv) उक्त जांच-प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, उप-नियम (1) के अधीन निर्गत अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, अधिनियम या पूर्व विधि के अधीन बकाये किसी राशि के भुगतान करने की, व्यवसायी के दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे जांच-प्रतिवेदन की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर निबंधन प्रमाण पत्र रद्द कर देगा।
- (ङ)(i) संबंधित अंचल प्रभारी, ऐसा प्रत्येक व्यवसायी पर, जिस पर धारा 20 की उप-धारा (3) के प्रावधान लागू होता हो, व्यवसायी से कारण दर्शाने हेतु अपेक्षा करते हुए की उसको दिया गया निबंधन प्रमाण पत्र क्यों नहीं रद्द कर दिया जाय एक सूचना तामील करेगा या करवाएगा।
- (ii) उप-खंड (i) के अधीन निर्गत सूचना में सुनवाई की तिथि अन्तर्विष्ट होगी जो सूचना निर्गत करने की तिथि से सामान्यतः पन्द्रह दिनों से अन्यून होगी।
- (iii) व्यवसायी को मामले में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करने एवं ऐसा साक्ष्य जिस पर व्यवसायी भरोसा करता हो पेश करने का अवसर देने के पश्चात्, संबंधित अंचल प्रभारी एक आदेश अभिलिखित करेगा, जिसमें व्यवसायी के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ करने के आधार, उसे इसके संबंध में अवगत कराने की रीति, दिया गया उत्तर, यदि कोई हो, और उस पर किया विनिश्चय अन्तर्विष्ट रहेगा; आदेश की एक सच्ची की प्रतिलिपि व्यवसायी को दे दी जायेगी।
- (iv) उप-खंड (iii) के अधीन अभिलिखित किसी आदेश के अनुसरण में यदि यह पाया जाय कि उप-नियम (4) के खंड (ख) के अधीन निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र रद्द किया जाना अपेक्षित है तो संबंधित अंचल प्रभारी आदेश की एक प्रति, इस आशय की अनुशंसा के साथ, उप-नियम (1) के अधीन निर्गत अधिसूचना में निर्दिष्ट प्राधिकारी को, आदेश की तिथि से सात दिनों के भीतर अग्रसारित करेगा तथा उक्त प्राधिकारी, उक्त आदेश तथा अनुशंसा के प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर निबंधन प्रमाण-पत्र रद्द कर देगा।
- (v) उप-खंड (4) के अधीन निबंधन प्रमाण-पत्र के रद्दकरण होने पर, उक्त प्राधिकारी उक्त रद्दकरण के सात दिनों के भीतर, संबंधित व्यवसायी को संसूचित कर देगा।
- स्पष्टीकरण— इस उप-नियम के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्ति “संबंधित अंचल प्रभारी” से अभिप्रेत है उस अंचल का प्रभारी जिसके क्षेत्राधिकार में व्यवसायी का व्यवसाय स्थल अवस्थित हो।
- (9) उप-नियम (1) से उप-नियम (8) में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, उप-नियम (1) के अधीन निर्गत अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अंचलों अथवा क्षेत्रों के संबंध में विभागीय वेब-साईट पर इलेक्ट्रॉनिक रीति से दाखिल किया गया निबंधन हेतु आवेदन उस रीति से किया एवं निपटारा जायेगा जिसे आयुक्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।”

2. यह अधिसूचना उसके निर्गमन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[सं० सं० वा०कर०/टी०आर०यू०/2011-12/03-छाया-3639(अनु०)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजित पुनहानी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

25 अगस्त 2011

एस0 ओ0 240, एस0 ओ0 239, दिनांक 26 अगस्त 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं० सं० वा0कर0/टी0आर0यू0/2011-12/03-छाया-3639(अनु०)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजित पुनहानी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

*The 25th August 2011*

S.O. 239, dated 26th August, 2011— In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 93 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments to the Bihar Value Added Tax Rules, 2005 :—

### Amendments

**1. Insertion of new Rule 3A after Rule 3 of the Bihar Value Added Tax Rule, 2005.**— After Rule 3 of the Bihar Value Added Tax Rule, 2005 the following new Rule 3A shall be inserted namely—

- “3A. Centralized Registration Unit.**— (1) Notwithstanding anything contained in rule 3, the application for registration in form A-1 or Form A-1A, as the case may be, in respect of dealers doing business in such circles or such areas as may be specified by the Commissioner in a notification issued in this behalf shall be presented before such authority as may be specified in the said notification.
- (2)(a) Every application under sub-rule (1) shall be presented by the dealer within seven days from the date of his becoming liable for payment of tax under the Act and shall be signed and verified in the manner provided in sub-rule (2) of rule 3.
- (b) Such application shall be submitted at the counter of the office of the authority specified in the notification issued under Sub-rule (1). The Incharge of the counter, after ascertaining that all the columns of the application have been properly filled in signed and verified shall—
- (i) grant the person a receipt in lieu thereof, and
- (ii) enter the particulars thereof in register VR-I maintained in the computer:
- Provided that the authority specified in sub-rule (1) may require the dealer to furnish such information as may be deemed fit.
- (3) In the case of a dealer to whom section 22 applies, an application for registration shall be accomplished by a correct and complete declaration in Form D-1 containing the particulars laid down in the Form along with two color photographs (13.5 cm X 2.5 cm) of the person or persons.
- (4)(a) On receipt of any application for registration, the authority specified in the notification issued under Sub-rule (1) shall generate a Taxpayer Identification Number in respect of the Circle having jurisdiction over the applicant in terms of the notification issued under Sub-section (2) of Section 10 of the Act.
- (b) Upon generation of the Taxpayer Identification Number under Clause (a), the applicant shall be granted a certificate of registration in form C-1 by the authority specified in the notification issued under sub-rule (1) at the earliest, preferably within fifteen days.

- (c) The certificate of registration issued under clause (b) shall be sent to the applicant by registered post within two days of its issuance to the address furnished by him in the application.
- (5)(a) Upon grant of the Certificate of Registration in Form C-I, the authority specified in the notification issued under Sub-rule (1) shall, within three days, forward a copy of the application for registration to the concerned Circle Incharge.
- (b) The concerned Circle Incharge shall, within a month, verify or caused to be verified the particulars furnished in the application. Thereupon, the concerned Circle Incharge shall forward a copy of the enquiry report to the authority specified in the notification issued under Sub-rule (1) within three days of the receipt of the enquiry report.
- (c) If, in terms of the enquiry report under clause (b), any of the particulars furnished in the application are found to be incorrect, or the applicant has misrepresented or suppressed any fact, the authority specified in the notification issued under Sub-rule (1) shall, after giving the dealer an opportunity of being heard, cancel the certificate of registration granted under sub-rule (4).

**Explanation.—** For the purposes of this sub-rule, the expression “concerned Circle Incharge” shall mean the Incharge of the Circle within whose jurisdiction the place of business of the dealer is situated.

- (6)(a) In case of such dealers who have got more places of business than one, situated in different circles in Bihar, or in case of a dealer having no fixed place of business in Bihar and who sells goods inside the State either direct or through agents or salesmen or otherwise, the application shall be made before the Commissioner or before the officer specially authorised in this behalf. After receipt of such application, the Commissioner or the officer specially authorised in this behalf shall direct the authority specified in the notification issued under Sub-rule (1) to register the dealer in the circle specified in the direction.
- (b) The provisions of sub-rule (1) to sub-rule (5) shall, apply mutatis mutandis to an application for registration under this sub-rule
- (7) (a) Notwithstanding anything contained in Rule 4, if a registration certificate granted under clause (b) of sub-rule (4) is lost, destroyed, defaced or becomes unintelligible, the holder of such certificate shall apply to the authority specified in the notification issued under sub-rule (1) for issuance of a duplicate copy of the certificate. Such an application shall be accompanied by—
  - (i) a receipted challan for rupees one hundred by way of fees;
  - (ii) an indemnity bond in Form B-1.
- (b) The said authority shall, in lieu of the certificate which was claimed to have been lost, destroyed, defaced or have become unintelligible, proceed to grant a duplicate certificate, which shall be stamped “Duplicate” in red ink.
- (8) (a) Notwithstanding anything contained in Rule 5, every dealer to whom a certificate has been granted under clause (b) of sub-rule (4) and to whom the provisions of Section 23 apply, shall inform in writing the appropriate authority specified in the notification issued under sub-rule (1) about the complete details necessitating action under Section 20.
- (b) Where the information furnished by a dealer under Section 23 or otherwise received by the authority specified in the notification issued under sub-rule (1) necessitates amendment of any information furnished by him in Form A-I or AI-A and subsequently entered in register in Form VR-I, the said authority shall

make suitable amendments in the said register in Form VR-I within fifteen days of the receipt of information under Section 23 or otherwise.

- (c) Where the information furnished by a dealer under Section 23 or otherwise received by the authority specified in the notification issued under sub-rule (1) necessitates amendment in a declaration furnished under Section 22, the dealer shall furnish to the said authority a revised declaration; until such revised declaration is furnished to the said authority the original declaration shall continue to be deemed valid and binding on such dealer.
- (d)(i) Every registered dealer to whom a certificate has been granted under clause (b) of sub-rule (4) and to whom Sub-section (2) of Section 20 applies, shall forthwith apply in Form A-II together with his registration certificate to the appropriate authority specified in the notification issued under sub-rule (1), for cancellation of his certificate of registration.
- (ii) On receipt of such application the authority specified in the notification issued under Sub-rule (1) shall within three days, forward a copy of the same to the concerned Circle Incharge.
- (iii) The concerned Circle Incharge shall, within a month, verify or caused to be verified the particulars furnished in the application. Thereupon, the concerned Circle Incharge shall forward a copy of the enquiry report to the authority specified in the notification issued under Sub-rule (1) within three days of the receipt of the enquiry report.
- (iv) Upon receipt of the enquiry report as aforesaid the authority specified in the notification issued under Sub-rule (1) shall cancel the registration certificate within seven days of receipt of such enquiry report without prejudice to the dealer's liability to pay any sum due under the Act or under the earlier law.
- (e)(i) The concerned Circle Incharge shall serve, or caused to be served, on every dealer to whom the provisions of Sub-section (3) Section 20 apply, a notice requiring the dealer to show cause as to why the certificate of registration granted to him not be cancelled.
- (ii) The notice under sub-clause (i) shall contain a date of hearing which shall ordinarily not be less than fifteen days from the date of issue of the notice.
- (iii) After giving the dealer a reasonable opportunity to be heard in the matter, and after allowing the dealer an opportunity to adduce such evidence as the dealer may rely upon, the concerned Circle Incharge shall record an order containing the grounds on which the dealer was proceeded against, the manner in which the dealer was made aware of that, the reply, if any, furnished and the decision thereon; a true copy of the order shall be made over to the dealer.
- (iv) If, pursuant to an order recorded under sub-clause (iii), it is found that the certificate of registration granted under clause (b) of sub-rule (4) is required to be cancelled, the concerned Circle Incharge shall forward a copy of the said order, alongwith a recommendation to that effect, to the authority specified in the notification issued under sub-rule (1), within seven days of the date of the order and the said authority, within three days of the receipt of the order and the recommendation, as aforesaid, shall cancel the certificate of registration.
- (v) Upon cancellation of the certificate of registration under sub-clause (iv), the said authority shall, within seven days of the cancellation as aforesaid, intimate the concerned dealer.

**Explanation.**—For the purposes of this sub-rule, the expression “concerned Circle Incharge” shall mean the Incharge of the Circle within whose jurisdiction the place of business of the dealer is situated.

- (9) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) to sub-rule (8), an application for registration filed electronic manner on the departmental website in respect of the Circles or areas specified in the notification issued under sub-rule (1) shall be made and disposed of in such manner as the Commissioner may, by notification, specify.”

2. This notification shall come into force with effect from the date of its issue.

[File No.-Va Kar/TRU/2011-12/03-Shadow-3639(ANU)]

By order of the Governor of Bihar,

RAJIT PUNHANI,

*Commissioner-Cum-Secretary,*

*Commercial Taxes Department.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 478-571+1000-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>